vkj- ,u- vkbZ- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- iath;u- la[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 14 vad % 15 y[kuÅ] 'kqdzokj 21 tqykbZ 2023 ls 27 tqykbZ 2023 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

संसद में सोनिया गांधी से उनकी सीट पर जाकर मिले प्रधानमंत्री मोदी, पूछा हाल-चाल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को संसद में सोनिया गांधी के पास गए और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, जब सांसद मणिपुर की स्थिति के ज्वलंत मुद्दे के बीच मानसून सत्र के पहले दिन इकट्ठे हुए थे। सोनिया गांधी ने कहा कि वह ठीक हैं। यह सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान तब हुआ जब दो कुकी महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया। यह सत्र संयुक्त विपक्ष के लिए भारत (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) की ताकत का परीक्षण करने का पहला अवसर भी है। बताया जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में कांग्रेस नेता के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की। सदन की दिन भर की बैठक शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने विभिन्न नेताओं का अभिवादन किया। जैसे ही वह विपक्षी नेताओं की बेंच पर पहुंचे, उन्होंने गांधी से संक्षिप्त बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। ऐसा तब हुआ है जब १८ जुलाई को

बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में भाग लेने के बाद जब वे दिल्ली लौट रहे थे तो सोनिया गांधी को एक फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग के दौरान अ क्सीजन मास्क पहने देखा गया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर नई दिल्ली जा रहे एक चार्टर्ड विमान को भोपाल हवाई अड्डे पर 'आपातकालीन' लैंडिंग करनी पड़ी। नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने की कथित घटना पर क्षोभ व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यह घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है। संसद का म नसून सत्र शुरू होने से पहले, मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने-अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री योगी ने 700 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को मिशन रोजगार के तहत UPPSC में चयनित ७०० अभ्यर्थियों को लोकभवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि अच्छे अधिकारी बनकर समाज की सेवा करें। बता दें इन चयनित अभ्यर्थियों का अलग-अलग विभागों में चयन हुआ है। बता दें कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने को लेकर सीएम योगी काफी सक्रिय नजर आते हैं, सीएम ने पारदर्शी व सही ढंग से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का कहना है

कि यूपी में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। सीएम योगी के ६ वर्ष के कार्यकाल में अब तक लाखों युवाओं को रोजगार मिल चुका है।

रोडवेज बस ने मारी आटो रिक्शा को टक्कर, चार लोगों की मौत

बाराबंकी। जिले के सफदरगंज क्षेत्र में लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर एक रोडवेज बस की टक्कर लगने से अ टो रिक्शा सवार चार लोगों

की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि लखनऊ से अयोध्या जा रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बुधवार की शाम सफदरगंज क्षेत्र में लखनऊ-अयोध्या राजमार्ग पर एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा में नौ लोग सवार थे, जिनमें से ४० वर्षीय महिला बिंदारा की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आठ अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से तीन लोगों-पिंकी (३८), विजय (४५) और चंदारा (६०) को चिकित्सकों की सलाह पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में घायल हुए पांच अन्य लोगों का बाराबंकी जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।

चीनी घोटाले का आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार

लखनऊ। चीनी घोटाले के आरोपी राजेन्दन सुब्बा नायडु को ईओडब्ल्यू ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ ला रही है। उसके खिलाफ चार जिलों में नौ मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी नायडु मेसर्स श्री वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई (तमिलनाडु) का निदेशक है। बरेली के देवरनिया, अमरोहा के हसनपुर, बहराइच के नानपारा व कोतवाली देहात और लखीमपुर खीरी के सम्पूर्णानगर, तिकोनिया व पसगवां थाने में उसके खिलाफ वर्ष २०२२ में दर्ज कुल नौ मुकदमों की विवेचना यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कर रही है। ईओडब्ल्यू को सुब्बा नायडु की तलाश थी, जबकि वह फरार था। ईओडब्लू टीम ने मंगलवार रात उसे तमिलनाडु के टेनी जिले के पीसी पटी थानाक्षेत्र में एमएमआर नगर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। यह मामला केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत नई दिल्ली स्थित शर्करा निदेशालय द्वारा वर्ष २०१६-२० में मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट (एमएईक्यू) कोटा के तहत निर्यात के लिए आवंटित चीनी के घोटाले से सम्बंधित है। मेसर्स श्री वेंकटेश्वर ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई ने इस कोटे के तहत आवंटित चीनी की चीनी मिल्स से उठान कर फर्जी परचेज अ फर व ई स्टाम्प शिपिंग बिल आदि के द्वारा भारत में ही अधिक दाम पर बेच दिया। जबकि आवंटित चीनी का निर्यात केंद्र सरकार द्वारा चीनी मिल्स से किए गए अनुबंध के अनुसार विदेशों में किया जाना था। ऐसा न किए जाने से केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी चीनी मिल्स को नहीं मिल सकी।

विवाहिता ने ससुर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

लखनऊ। आशियाना थाने में एक विवाहिता ने ससुर समेत नंदोई पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता का कहना है कि आरोपितों ने उसे बंधक बना घिनौनी हरकत की। विरोध किए जाने पर उसे जिंदा जलाने का भी प्रयास किया है। इस बात से नाराज ससुर और नन्दोई मोहम्मद इरशाद, जमील और शोएब ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की नीयत से पेट्रोल छिड़क जिंदा जलाने का भी प्रयास किया। इस सम्बन्ध में पीड़िता ने लखनऊ पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर से शिकायत की। जिनके निर्देश पर आशियाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, जानलेवा हमले के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मूलरुप से आयोध्या जनपद की रहने वाली पीड़िता का निकाह वर्ष २०२१ में साहेल नगर निवासी मोहम्मद वासिम राजा से हुआ था। पीड़िता का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग आए-दिन अतिरिक्त मांगों के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि ससुर मोहम्मद वसीक उस पर गलत नीयत रखता था। मौका पाते ही आरोपित उससे छेड़खानी भी करता था। पीड़िता ने मायके वालों को आरोपितों की हरकत बताई थी।

यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। दिल्ली की राउज कोर्ट ने आज दोपहर १२रू३० बजे सुनवाई शुरू की। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी गई थी। अदालत ने दोनों आरोपियों को २५,००० रुपये के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने १५ जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के अनुसार आरोप पत्र आईपीसी की धारा ३५४, ३५४डी, ३४५ए और ५०६ (१) के तहत दायर किया गया था। पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं। एक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था और एक नाबालिग पहलवान के लिए रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई है। दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

सम्पादकीय

हिल गया भारत

मणिपुर के उस वीडियो ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया जिसमें दो महिलाओं को नंगा करके मर्दों के समूह ने सड़क पर दौड़ाया, उनको मारा पीटा और रेप किया। इस घटना ने जहां मानवता को शर्मसार किया है वहीं इस वारदात का एक सच और है जो आपको झकझोर कर रख सकता है। क्या आपको पता है जिन महिलाओं के साथ वीडियो में जो कुछ हो रहा है उनमें से एक महिला कारगिल के हीरो की पत्नी है? जी हां कारगिल युद्ध में जिन जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लिए युद्ध लड़ा आज देश के कुछ दरिंदे उनकी ही पत्नी की ये दुर्दशा कर रहे है। सोचिए उस फौजी की मनोदशा क्या होगी जिसकी पत्नी के साथ बर्बता हुई। भारत मां की लाज बचाने वाला वो फौजी देश में पलने वाले दरिंदों से अपने पारिवार को न बचा सका। दो महिलाओं की नग्न परेड का वीडियो अ नलाइन सामने आने के दो दिन बाद, अब यह खुलासा हुआ है कि दोनों पीड़ितों में से एक कारगिल नायक की पत्नी है। एक साक्षात्कार में, नग्न परेड करने वाली दो महिलाओं में से एक के पति ने इस बात पर अफसोस जताया कि यद्यपि उसने देश की रक्षा की, लेकिन वह अपनी पत्नी को अपमानित होने से नहीं बचा सका। उन्होंने बताया, 'मैंने कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका में भी था। मैंने देश की रक्षा की लेकिन मुझे दुख है कि मैं अपनी पत्नी और साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका।' जनजातीय महिलाओं के साथ चार मई को हुई इस घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया जिसके बाद इसकी देशभर में निंदा की गई। एक पीड़िता के पति भारतीय सेना की असम रेजिमेंट में सूबेदार के तौर पर सेवा प्रदान कर चुके हैं। पीड़िता के पति ने एक समाचार चौनल को बताया, ''मैंने करगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी और भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में श्रीलंका में भी तैनात रहा था। मैंने देश की रक्षा की, लेकिन मैं निराश हूं कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, मैं अपने घर, अपनी पत्नी और साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं कर सका... मैं दुखी और उदास हूं। उन्होंने कहा कि चार मई की सुबह एक भीड़ ने इलाके के कई घरों को जला दिया, दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया और उन्हें लोगों के सामने गांव की पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर किया। पूर्व सैन्यकर्मी ने कहा, ''पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को कड़ी सजा मिले, जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं को अपमानित किया।'' वीडियो सामने आने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड की घटना मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को ११ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ४ मई की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसमें राज्य में दो समुदायों के बीच अशांति के बीच मणिपुर में २–३ महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। इस घटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है और कहा है कि यह देश के लोगों के लिए शर्म की बात है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि आरोपियों से सख्ती से निपटा जाएगा और वे मौत की सजा पर भी विचार कर रहे हैं। यह वीडियो, जो बुधवार को सामने आया, कथित तौर पर ४ मई को कांगपोकपी इलाके में एक बैठक के दौरान राज्य में हुए हंगामे के एक दिन बाद शूट किया गया था। पुरुषों के एक समूह ने दो कुकी–जोमी महिलाओं का यौन उत्पीड़न जारी रखा, जबकि उन्हें वीडियो में नग्न परेड कराया गया था। थौबल के मैतेई शासित घाटी क्षेत्र में हुई घटना के बाद, सीमावर्ती कांगपोकपी जिले के एक पुलिस मुख्यालय में एक आपत्ति दर्ज की गई और एक शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मामला थौबल स्थित पुलिस मुख्यालय को भेजा गया। मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के वीडियो के दो दिन बाद, स्थानीय लोगों ने वायरल वीडियो में देखे गए कथित आरोपियों में से एक ह्यूरिम हेरादास सिंह के घर में आग लगा दी। २० जुलाई को इंफाल में महिलाओं ने मणिपुर वायरल वीडियो मामले के एक आरोपी का घर जला दिया। मामले में अब तक चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यह घटना पूर्वोत्तर राज्य में ३ मई को जातीय हिंसा भड़कने के एक दिन बाद कांगपोकपी जिले के एक गांव में हुई। दूसरी ओर, भयावह फुटेज बुधवार को सामने आया और इंटरनेट प्रतिबंध हटने के बाद वायरल हो गया।

देश में क्या है शर्म? सभी है दोषी!

अजीत द्विवेदी....। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे मणिपुर के वीडियो को लेकर बहुत परेशान हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे बढ़ कर कहा है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल है कि दोषी कौन है? मणिपुर की इंफाल घाटी के मैती बहुल थौबल जिले की वह भीड़, जिसके सामने दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया या वो लोग जिन लोगों ने महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई या उनके साथ सामूहिक बलात्कार में शामिल हुए? क्या कांगपोक्पी जिले की पुलिस दोषी नहीं है, जिसने १८ मई को एफआईआर दर्ज किया और ठीक दो महीने बाद वीडियो वायरल होने तक कोई कार्रवाई नहीं की? क्या थौबल जिले की पुलिस के सिर यह अपराध नहीं आएगा, जिसकी आंखों के सामने कुकी–जोमी समुदाय के एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया? घटना चार मई की है, जब वीडियो में दिख रही २० साल की युवती की आंखों के सामने उसके पिता और भाई की हत्या कर दी गई और पूरा परिवार उजाड़ दिया गया। दोनों महिलाओं को आतातायी भीड़ पुलिस के हाथों से खींच कर ले गई और उनको निर्वस्त्र किया, उनके साथ बलात्कार किया। तो क्या वह पुलिस इस अपराध में शामिल नहीं मानी जाएगी, जिसके सामने यह अत्याचार हुआ? फिर किन दोषियों को तलाश किया जा रहा है? चीफ जस्टिस को कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट से ही क्यों नहीं शुरू करते, जिसके एक आदेश के बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी है तो मुख्यमंत्री से शुरू क्यों नहीं करते, जिसके राज में स्त्रियों के साथ ऐसी बर्बर और अमानवीय घटना हो रही है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने भारत शर्मसार हो रहा है? दो महिलाओं के साथ अमानवीयता का वीडियो सामने आने के १२ घंटे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। यह कितने शर्म की बात है! चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि घटना के ७७ दिन के बाद राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि पहली गिरफ्तारी हुई है! क्या राज्य के मुख्यमंत्री को इस घटना की पहले से जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी नहीं थी तो राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकार के नाते उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वीडियो में दिख रहे दरिंदों को गिरफ्तार करने से पहले थौबल और कांगपोक्पी जिले की समूची पुलिस फोर्स पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जिन्होंने सब जानते बूझते कोई कार्रवाई नहीं की। जिस मैती बहुल थाना क्षेत्र की यह घटना है वहां के सभी पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस कुकी–जोमी बहुल थाना क्षेत्र में जीरो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस थाना क्षेत्र के भी सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह

कोई सामान्य अपराध नहीं है, जिसमें दो–चार दोषियों की गिरफ्तारी हो और मामला रफा–दफा हो। यह समूचे सिस्टम के विफल होने की घटना है। अगर आप घटना की क्रोनोल जी सुनेंगे तब समझ में आएगा कि किस तरह से पूरे सिस्टम ने इस घटना को होने दिया और उसके बाद दबाए रखा। मणिपुर में तीन मई को कुकी और मैती समुदायों के बीच हिंसा की शुरुआत हुई थी। उसके अगले दिन चार मई को थौबल जिले के एक मैती बहुल इलाके में कुकी–जोमी समुदाय के एक परिवार के घर पर भीड़ ने हमला किया। परिवार के पांच लोग जान बचा कर भागे और पुलिस के पास पहुंचे। लेकिन भीड़ ने पुलिस के हाथों से उनको छीन लिया और दो पुरुष सदस्यों की मौके पर ही हत्या कर दी। उसके बाद दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। किसी तरह से महिलाएं वहां से भाग कर कुकी–जोमी बहुलता वाले इलाके में पहुंचीं और पुलिस के पास जाकर मुकदमा दर्ज कराया। चार मई की घटना पर अज्ञात लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर १८ मई को दर्ज की गई और मुकदमे की फाइल थौबल भेजी गई, जहां घटना घटित हुई थी। इस घटना का वीडियो बनाया गया था और सैकड़ों लोग नंगी आंखों से इस घटना गवाह बने थे। फिर भी पूरे मणिपुर में मुर्दा शांति बनी रही। हैरानी की बात है कि शांति बहाली के प्रयास के लिए २६ मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए। वे कुकी और मैती दोनों समुदायों को राहत शिविरों में गए। क्या किसी ने उनको इस घटना के बारे में नहीं बताया? अगर नहीं बताया है तो अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस, प्रशासन और खुफिया पुलिस के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना की जानकारी हजारों लोगों को थी। पुलिस के लोग घटना के बारे में जानते थे। निश्चित रूप से राजनीतिक आकाओं को इसकी जानकारी होगी। लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मणिपुर में पिछले ढाई महीने से चल रही हिंसा समाप्त क्यों नहीं हो रही है? हिंसा कैसे समाप्त होगी, जब इस तरह की वीभत्स घटना पर भी पुलिस और प्रशासन आंखें बंद किए रहेगा? इससे अपराधियों के हौसले बढ़े और दूसरी ओर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया की भावना भी प्रबल हुई। हिंसा भड़कने के दूसरे दिन हुई इस अमानवीय घटना की प्रतिक्रिया में न जाने कितनी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया। अगर पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई की होती और दोषियों को गिरफ्तार किया होता तो शायद हिंसा को रोकने में कामयाबी मिलती। लेकिन इस वीभत्स घटना को झूठे जातीय गर्व का चोला पहना दिया गया। इस्लामी देशों से लेकर अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में भी जातीय, नस्ली हिंसा होती है लेकिन ऐसी वीभत्स घटना उन देशों से भी सुनने को नहीं मिलती हैं। पहली नजर में यह पुलिस और प्रशासन की विफलता दिखती है लेकिन असल में यह एक समाज के नाते पूरे देश की और हर नागरिक की विफलता है। जिस समाज में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है वह समाज कहीं से सभ्य कहे जाने लायक नहीं है। हम बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर माला पहना कर उनका स्वागत करते हैं। हम स्त्रियों का यौन उत्पीड़न करने वाले को इसलिए बचाते हैं कि वह एक खास दल का सांसद है। फिर हम कैसे ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं? हम कैसे एक समाज के रूप में विफल रहे हैं यह इस बात से भी पता चलता है कि सैकड़ों लोगों की जिस भीड़ के सामने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस भीड़ में किसी की अंतरात्मा नहीं जागी। किसी ने आगे बढ़ कर उन स्त्रियों के शरीर पर एक कपड़ा नहीं डाला। यह सही है कि दो निर्वस्त्र स्त्रियां वीडियो में दिख रही हैं लेकिन असल में नंगे वे सैकड़ों लोग थे, जो उस भीड़ का हिस्सा थे। वे जीते जागते लोग थे लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी थी। सोचें, उस समय उन स्त्रियों का मन कैसे चीत्कार रहा होगा? क्या वे धरती फट जाने की कामना कर रही होंगी या पूरी सृष्टि के नष्ट हो जाने की प्रार्थना कर रही होंगी? घटनास्थल के हजारों मील दूर आज जिन लोगों का सचमुच कलेज फट रहा है वे भी उन महिलाओं की वास्तविक पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यह पाप हम सब पर भारी है, सब इस पाप के भागीदार हैं, कोई क्षमा का हकदार नहीं है।...साभार

'मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना' प्रदेश के किसानों के लिए बन सकती है सौगात

लखनऊ। योगी–२.० के लिहाज से 'मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना' प्रदेश के किसानों के लिए सौगात बन सकती है। योजना की उपयोगिता के मद्देनजर ही सरकार अब इसे सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं, पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करेगी। इसीलिए योजना के बाबत प्रस्तावित बजट ७५ करोड़ से बढ़ाकर ३५० करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किसान के खेत की फसल को पशुओं से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की योजना है। इसके तहत लगाई जाने वाली सोलर फेंसिंग की बाड़ में मात्र १२ बोल्ट का करंट प्रवाहित होगा। इससे सिर्फ पशुओं को झटका लगेगा। कोई क्षति नहीं होगी। हल्के करंट के साथ सायरन की आवाज भी होगी। इससे छुट्टा या जंगली जानवर मसलन नीलगाय, बंदर, सुअर आदि खेत मे खड़ी फसल को क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। इसके लिए सरकार लघु–सीमांत किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत ६० फीसद या

१.४३ लाख रुपये का अनुदान भी देगी। कृषि विभाग इस योजना का ड्राफ्ट तैयार कर चुका है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पशु खेत में खड़ी फसल का नुकसान तब अधिक करते हैं जब उनको पास में कुछ खाने को नहीं मिलता। गोचर भूमि इसके लिए जरूरी है। गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग ११ जुलाई से अभियान चल रहा है। यह अभियान २५ अगस्त तक चलेगा। उल्लेखनीय है कि छुट्टा पशुओं की यह समस्या कमोबेश पूरे प्रदेश में एक जैसी है। विपक्ष समय–समय पर इस समस्या को लेकर तंज कसता रहता है। पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी फील्ड में इस बाबत सुनना पड़ता है। अगले साल लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा न बने, इसमें ये कदम मददगार बनेंगे।

अयोध्या मस्जिद का निर्माण अब टुकड़ों में

लखनऊ। राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मिली जमीन पर मस्जिद, अस्पताल और सामुदायिक रसोई समेत एक वृहद परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे 'इंडो–इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट' ने धन के अभाव के चलते अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ट्रस्ट अब मस्जिद समेत इस परियोजना से संबंधित अन्य इमारतों का निर्माण टुकड़ों में कराएगा। उसने पूर्व में इस परियोजना की शुरुआत मस्जिद के बजाय अस्पताल के निर्माण से करने का फैसला किया था, लेकिन इस पूरी परियोजना को एक साथ शुरू करने के वास्ते डेवलपमेंट चार्ज समेत करोड़ों रुपये बतौर शुल्क चुकाने पड़ेंगे, जिसके लिए ट्रस्ट के पास धन नहीं है। यही कारण है कि ट्रस्ट ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए टुकड़ों में काम कराने का निर्णय लिया है। 'इंडो–इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट' के सचिव एवं प्रवक्ता अतहर हुसैन ने रविवार को 'पीटीआई–भाषा' को बताया, "धन की कमी की वजह से अभी हमने परियोजना को रोक रखा है। इस मुश्किल के बावजूद हम इस परियोजना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि रणनीति में बदलाव करते हुए उसे छोटे–छोटे हिस्सों में बांटकर काम करेंगे। हुसैन ने कहा, अब हम अस्पताल के बजाय सबसे पहले नये सिरे से मस्जिद का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा करेंगे। मस्जिद के निर्माण में अपेक्षोंत काफी कम

धन खर्च होगा, जिसका इंतजाम करना आसान रहेगा। उन्होंने कहा, हम पहले मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है और हर आदमी इस परियोजना को मस्जिद के नाम से ही जानता है। इसलिए ट्रस्ट अब मस्जिद के निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है। हुसैन ने बताया, मस्जिद निर्माण की लागत इस पूरी परियोजना की कुल लागत का पांच फीसद हिस्सा भी नहीं है। करीब १५,००० वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाली इस मस्जिद के निर्माण पर आठ से १० करोड़ रुपये खर्च होंगे। मस्जिद की बिजली संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सौर पैनल से होगी, जो इसके गुंबद पर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश थी कि मस्जिद से पहले अस्पताल का निर्माण कराया जाए, लेकिन यह ३०० करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जहां मस्जिद का निर्माण प्रस्तावित है, वहां पहले से ही कई मस्जिदें हैं। ऐसे में हमारी सोच थी कि पहले एक चौरिटी अस्पताल और सामुदायिक रसोईघर बनाया जाए, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, जो फिलहाल ट्रस्ट के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और 'इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट' के मुख्य न्यासी जुफर फारूकी ने बताया, इस परियोजना के वास्ते चंदा इकट्ठा करने के लिए अभी व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रयास किए गए हैं। जनता से चंदा जुटाने के लिए ट्रस्ट के लोग अगले महीने से देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा कि धन्नीपुर में पूरी परियोजना को मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपये की जरूरत पड़ेगी और इस रकम को इकट्ठा करने के लिए बोर्ड इसी महीने के अंत में बैठक कर रणनीति बनाएगा।

लोकसभा में अतीक अहमद को दी गई श्रद्धांजलि

लखनऊ। लोकसभा में दो वर्तमान सदस्यों रतन लाल कटारिया एवं बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर और अतीक अहमद समेत ग्यारह पूर्व सदस्यों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुरुवार को श्रद्धांजलि दी गयी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दो वर्तमान सदस्यों और ग्यारह पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अंबाला संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद रतन लाल

कटारिया (७१) का निधन १८ मई चंडीगढ में हुआ। वह कई समितियों के सदस्य रहे थे। वह हरियाण विधानसभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने कहा कि बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। उनका निधन ३० मई को ४८ साल की उम्र में गुरुग्राम में हुआ। अध्यक्ष ने कहा कि सदन वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है।

सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह

लखनऊ। सियाचिन ग्लेशियर में स्थित सेना के बंकर में बुधवार को आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में टेंट भी आ गए। जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए हैं। इसके अलावा कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सेना के जवानों ने आग की चपेट में आए घायल सैन्य कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सियाचिन में लखनऊ निवासी रेजिमेंटल मेडिकल अ फिसर कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हुए हैं। टेंट में आग लगने से हुए हादसे में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह यूपी की राजधानी लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सेना के बंकर में यह आग शार्ट सर्किट के कारण लगना बताई जा रही है।

मंडी समितियां किसानों को देंगी पौधे

लखनऊ। मंडी समितियां २५ लाख पौधे लगाएंगी। इस अभियान में किसानों को शामिल किया जाएगा। जिन्हें एक–एक पौधा रोपण के लिए दिया जाएगा और सत्यापन कराया जाएगा। अभियान की शुरुआत निदेशक अंजनी कुमार सिंह उप मंडी स्थल बंथरा से खुद पौधारोपण कर सकेंगे। मंडी परिषद को इस बार २५ लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। जो प्रदेश की २५१ मंडी समिति के परिसर में लगाए जाएंगे। इस बार जो पौधे मंडी में रोपे जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए ट्री–गार्ड भी लगाए जाएंगे। उप निदेशक मुख्यालय चंदन कुमार पटेल ने बताया कि साथ ही मंडी से जुड़े किसान इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। जिन्हें एक–एक पौधा आधार कार्ड लेकर निशुल्क वितरित करेंगे और रोपण के बाद

सत्यापन कराएंगे। एक–एक पौधा होने से संरक्षण अच्छे से करेंगे। २१–२२ जुलाई को पौधरोपण होगा। बंथरा उप मंडी स्थल में निदेशक अंजनी कुमार सिंह पौधरोपण करेंगे।

विभागों ने सांसद आदर्श ग्राम का नहीं दिया प्लान

लखनऊ। जिले में सांसद आदर्श ग्राम का विकास तो दूर विभागों ने विलेज डेवलपमेंट प्लान तक नहीं दिया है। जिसमें विकास कार्यों की १० प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। जिला कृषि अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है। सरोजनी नगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत लतीफनगर सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित है। जहां, प्राथमिकता से विकास कार्य कराना है। जिसकी लोक निर्माण, प्रशासन, जल निगम, कृषि, जिला पंचायत, नेडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व वन विभाग को जिम्मेदारी मिली है। जो विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाकर अपनी एक–एक योजना पर कार्य करेंगे। इस योजना का नोडल जिला कृषि अधिकारी तेग बहादुर सिंह को बनाया गया है। जिन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से विलेज डेवलपमेंट प्लान मांगा था। जो अब तक विभागों ने नहीं दिया है। इस लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल ने नाराजगी जताई है और नोडल अधिकारी ने एक सप्ताह का समय देकर प्लान मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है।

बीच सड़क पर पति ने प्रेमिका के संग मिलकर पत्नी को पीटा

लखनऊ। विभूतिखंड थानाक्षेत्र से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो महिलाएं व एक पुरुष आपस में मारपीट करते दिखाई पड़ रहें हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में एक युवक प्रेमिका के संग मिलकर पत्नी को मारता दिखाई पड़ रहा है। वायरल वीडियो में साफतौर पर दिखाई पड़ रहा है कि पहले तीनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन, इसी बीच दोनों महिलाएं उग्र होकर आपस में बीच सड़क पर मारपीट करने लगती है। इस दौरान युवक भी प्रेमिका के संग पत्नी को पीटने लगता है। वहां तमाशा देख लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। विभूतिखंड प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि वीडियो सामने आया है। घटना के संदर्भ में किसी ने भी लिखित शिकायत नहीं दी है। शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।

'इंडिया' के लिए आसान नहीं उत्तर प्रदेश की राह

लखनऊ। बेंगलुरु में एक बैठक में, २६ विपक्षी दलों ने अगले साल के लोकसभा चुनावों के लिए अपने मेगा बीजेपी विरोधी मोर्चे, इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस) की घोषणा की। हालाँकि, गठबंधन के नाम को अंतिम रूप देने के बावजूद, सीट वितरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में। अब समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस की साझेदारी पर चर्चा करते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में ३० से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी आधी से कम सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की मांग रहा है। जनवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी भी समाजवादी पार्टी से एक सीट की उम्मीद कर रहे हैं। नतीजतन, सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ८० सीटें साझा करने की होगी। मायावती का ऐलान उधर, मायावती ने ऐलान किया कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने का इरादा जताया। पंजाब और अन्य राज्यों में वह संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। बसपा दोनों ही गठबंधनों से समान दूरी बनाकर रखना चाहती है। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को जवाब दिया है। यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी मानसिकता नहीं बदली है। उन्होंने ष्इंडिया इज इंदिराष नारे का उल्लेख किया और विपक्षी गठबंधन द्वारा 'इंडिया' नाम चुनने की आलोचना की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह विपक्षी गठबंधन मोदी को हटाने में सफल नहीं होगा, क्योंकि वे ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने २०१४, २०१७ और २०१६ में गठबंधन किया लेकिन सफल नहीं हुए। जनता अच्छी तरह से जानती है कि देश के हित के लिए केवल मोदी जी ही काम कर सकते हैं, यही कारण है कि उन्हें तीसरी बार पीएम बनाने

के लिए सभी लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत पर जोर दिया है। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने कहा कि जो लोग देश को बचाना चाहते हैं और भाजपा की तानाशाही का विरोध करते हैं वे बेंगलुरु में एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है और सभी को तय करना होगा कि वे कहां खड़े हैं। साजन ने उन सभी का स्वागत किया जो भाजपा को हराने के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मायावती को यह तय करने की जरूरत है कि वह भारत के साथ हैं या एनडीए के साथ। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव पहले ही सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का इरादा जता चुके हैं। इंडिया फ्रंट के बारे में सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी भूमिका तय नहीं हुई है, लेकिन इच्छा सीटें हासिल करने की नहीं बल्कि बीजेपी को उखाड़ने की है. उन्होंने मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके इस फैसले से विपक्ष को कोई नुकसान नहीं है। इन घटनाक्रमों के जवाब में, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इंडिया फ्रंट ने विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी है, और गठबंधन में सभी दल मजबूत हैं। यूपी में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। राजपुत ने कहा कि जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उन्हें भविष्य में जनता सबक सिखाएगी। जहां तक घ्सीट बंटवारे की बात है तो यह नरेंद्र मोदी के अहंकार के खिलाफ सद्भाव और सहिष्णुता पर आध ारित गठबंधन है। सीट बंटवारा बिना किसी समस्या के आसानी से सुलझा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा दिल दिखाया है। विपक्षी एकता और इंडिया को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद का मोह त्यागा है। इसका फायदा उसे सीट बंटवारे में मिल सकता है।

इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को जिन राज्य में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए १० से १५ सीट छोड़ने को तैयार हो गए हैं। लेकिन आंकड़ों को लेकर अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि गठबंध न को लेकर कांग्रेसी नेताओं में ज्यादा उलझन है। पार्टी के उत्तर प्रदेश के ज्यादातर नेता अकेले ही चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। खुलकर कुछ कहने की बजाय वह आलाकमान के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं का दावा है कि अखिलेश यादव को लेकर ओबीसी और मुस्लिम वोटों में नाराजगी है। इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। पार्टी के नेताओं का यह भी दावा है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में एक अंडरकरेंट है। कर्नाटक चुनाव के बाद पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बदली है। हालांकि, यह बात भी सच है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में २.३३ः वोट शेयर मिले और २ सीटों पर जीत हासिल की थी। २०१६ में भी कांग्रेस सिर्फ रायबरेली से जीतने में कामयाब रही। राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी में हार गए थे। समाजवादी पार्टी (एसपी), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और अजित सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के श्महागठबंधनश के बाद भी बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने ६४ सीटों (६२रू बीजेपी और २रू अपना दल—एस) पर जीत हासिल की। विपक्षी तिकड़ी का गठबंधन केवल १५ सीटें हासिल कर सका, जबकि मायावती की बसपा ने १० सीटें जीतीं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को केवल ५ सीटें मिलीं। पूरे राज्य में एनडीए को ५० फीसदी से ज्यादा वोट शेयर मिला। विशेष रूप से, भाजपा ने ५०ः से अधिक वोट शेयर के साथ राज्य में ४० लोकसभा सीटें जीतीं। ये सीटें थीं कैराना, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झाँसी, हमीरपुर, फतेहपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, बहराईच, कैसरगंज, गोंडा, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशी नगर, देवरिया, बांसगाँव, सलेमपुर और वाराणसी। बसपा द्वारा अपने दम पर २०२४ का चुनाव लड़ने का फैसला करने और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के भाजपा से हाथ मिलाने के साथ हाथ मिला लिया है। सवाल यह है कि क्या एसपी—आरएलडी गठबंध ान राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से अकेले लड़ाई लड़ेगा या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी राज्य के पश्चिमी हिस्से में अपना विस्तार करने के लिए आरएलडी को लुभाने की कोशिश कर रही है। राजनीति में जो सामने से दिखता है, पर्दे के पीछे भी वैसा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कागज पर विपक्षी एकता जितनी मजबूत नजर आ रही है, उतना इसका जमीन पर प्रभाव रहेगा, इसको लेकर सवाल बरकरार है। हालांकि विकास की बात तो सभी दल करते हैं, लेकिन चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को जीतने में कामयाब होती है, चुनावी परिणाम भी उसी के पक्ष में जाते हैं। और यही तो प्रजातंत्र है।

राहुल गांधी ने गुजरात HC के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर कल सुनवाई करेगी। गांधी ने आपराधिक मामले में सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले में दोषसिद्धि के कारण उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। आपराधिक मानहानि का मामला २०१६ के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी पर दायर किया गया था। ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों का जिक्र करते हुए गांधी ने पूछा था कि 'सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है? २३ मार्च, २०२३ को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और २ साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।ष् लोकसभा के सदस्य के रूप में। हालाँकि, उनकी सजा निलंबित कर दी गई, और उन्हें उसी दिन जमानत भी दे दी गई ताकि वह ३० दिनों के भीतर अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील कर सकें। ३ अप्रैल को गांध ी ने अपनी दोषसिद्धि पर आपत्ति जताते हुए सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की, जिसे २० अप्रैल को खारिज कर दिया गया। हालांकि, सूरत सत्र न्यायालय ने ३ अप्रैल को गांधी को उनकी अपील के निपटारे तक जमानत दे दी।

मणिपुर वीडियो पर प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी को घेरा

नई दिल्ली। मणिपुर वीडियो पर स्मृति ईरानी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह मुद्दा महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री ने तभी उठाया जब वह दबाव में आ गईं। उन्होंने ईरानी को सबसे अक्षम मंत्री बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। ४ मई का एक वीडियो बुधवार को सामने आया जिसमें युद्धरत समुदायों में से एक की दो महिलाओं को कुछ पुरुषों द्वारा नग्न परेड करते हुए दिखाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद ईरानी ने इस घटना को षनिंदनीय और सर्वथा अमानवीयष बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कभी इस पर बात नहीं की, लेकिन अब जब उन पर दबाव है, तो वह कहती हैं कि उन्होंने सीएम से बात की है। देश के सबसे अक्षम मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।" चतुर्वेदी ने कहा कि श्घटना देश को शर्मसार करती हैश् और उन्होंने इस मुद्दे को आज संसद में उठाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कल देश के सामने मणिपुर से दो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध का वीडियो आया। ऐसी घटना देश को शर्मसार करती है। एक महिला सांसद होने के नाते मैं मणिपुर पर चर्चा चाहती हूं। पीएम को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और सदन में बोलकर लोगों को जवाब देना चाहिए। संसद में आज यह पहला मुद्दा होगा। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ष्मणिपुर से आया दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भयावह वीडियो निंदनीय और पूरी तरह से अमानवीय है। सीएम एन बीरेन सिंह जी से बात की, जिन्होंने मुझे सूचित किया है कि जांच अभी चल रही है और आश्वासन दिया है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा।ष् 'इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम' (आईटीएलएफ) के बृहस्पतिवार को प्रस्तावित मार्च से एक दिन पहले यह वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बताया कि थाउबल जिले के नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने में अज्ञात सशस्त्र बदमाशों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

सोमवती अमावस्या पर सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक

लखनऊ। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय लगने वाले सावन मास के दूसरे सोमवार को सोमवती (सोमवारी) अमावस्या के सुखद सर्वार्थ सिद्धि विशेष योग में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में रुद्राभिषेक व हवन कर देवाधिदेव महादेव से लोकमंगल की कामना की। सावन मास के प्रथम दिन भी गोरक्षपीठाधीश्वर ने रुद्राभिषेक कर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि की प्रार्थना की थी। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सावन के दूसरे सोमवार (संयोगवश सोमवती अमावस्या भी) को भी उन्होंने भगवान शंकर की विशेष

आराधना कर चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना की। सोमवार प्रातः गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भोलेनाथ को विल्व पत्र, कमल पुष्प आदि अर्पित करने कर बाद दूध, एवं फल के रस से रुद्राभिषेक किया। मठ के मुख्य पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी व अन्य आचार्य एवं पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कराया। रुद्राभिषेक के बाद उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती की। विधि विधान से पूर्ण हुए अनुष्ठान के उपरांत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय, समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगलकामना की।

पति पर महिला का 'हलाला' के नाम पर शारीरिक शोषण करने का आरोप

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक महिला का 'हलाला' के नाम पर शारीरिक शोषण करने के आरोप में उसके शौहर समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नेपाल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि महिला की शिकायत पर बुधवार रात उसके पति शाहिद और सास सहित चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ३७६डी (बलात्कार), ४९८ए (गैरकानूनी मांग पूरी करने के लिए महिला को परेशान करना), ३२३ (जानबूझकर चोट पहुंचाना), ५०४ (जानबूझकर अपमान करना), धारा ५०६ (आपराधिक धमकी) और मुस्लिम महिला अधिनियम २०१९ की धारा ३ और ४ (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि करीब १२ साल पहले निघासन कोतवाली के एक व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था और शादी के बाद से उसे तीन बार तीन तलाक का सामना करना पड़ा, जबकि उसे अपने पति के बहनोई के साथ दो बार हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के दो साल बाद उसके पति ने एक लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे तीन तलाक दे दिया। हालांकि, उसने अपने जीजा के साथ 'हलाला' के बाद उससे दोबारा शादी कर ली थी। बाद में वर्ष २०२० में भी महिला को इसी सदमे से गुजरना पड़ा। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि इसी महीने चार जुलाई को उसके पति ने उसे फिर से तीन तलाक दे दिया। जब उसके माता–पिता ने उससे बात की, तो उसने एक बार फिर 'हलाला' पर जोर दिया और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नेपाल सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि महिला की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पत्न्नी को तलाक देने के बाद उससे तुरंत निकाह नहीं कर सकता, बल्कि परित्य्यक्ता को किसी दूसरे मर्द से निकाह करके उससे शारीरिक सम्बन्ध्ध बनाने होते हैं। उसके बाद अगर वह व्यक्ति उस महिला को तलाक देता है, तभी पहला पति उससे निकाह कर सकता है।

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को दो साल की सजा, 2,500 रुपये का जुर्माना

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को नफरती भाषण मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खान को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के प्रश्न पर आजम खान के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया। आजम खान न्यायिक अभिरक्षा में हैं। हेट स्पीच मामले में एलपी–एमएलए कोर्ट का फैसला आने पर दोषी पाए गए आजम खान को २ साल की सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। आजम खान के वकील अब उनकी जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं। अभियोजन पक्ष के सहायक अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने कहा, "आजम को तीन धाराओं में सजा सुनाई गई है। दो धाराओं में २–२ साल की सजा सुनाई है। जबकि, एक धारा में एक महीने की सजा सुनाई गई है। आजम ने मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। शनिवार को अदालत ने आजम खान पर इस मामले में दोष सिद्ध कर दिया। फैसला सुनाने से पहले उन्हें अदालत में तलब किया गया।

आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ पहुंचे। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस मुकदमे में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है। १७१जी में ५०० रुपये का जुर्माना और एक महीने की जेल, ५०५(१)बी में १००० रुपये जुर्माना और दो साल की सजा, १२५ में १००० रुपये का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि २०१९ के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान के खिलाफ थाना शहजादनगर के धमोरा में एक चुनावी जनसभा में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर एक मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था। आजम खान पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। पिछले साल रामपुर की एक एमपीध्एमएलए कोर्ट ने आजम खान को २०१९ के एक अन्य नफरती भाषण मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

अब दिल्ली अध्यादेश पर संविधान पीठ में सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका पर फैसले के लिए बृहस्पतिवार को इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामले को बड़ी पीठ को सौंपने का विस्तृत आदेश आज दिन में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और दिल्ली सरकार की तरफ से क्रमशरू पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे व अभिषेक सिंघवी की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "हम इसे संविधान पीठ को भेजेंगे। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए। शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। केंद्र ने १९ मई को दिल्ली में 'ग्रुप–ए' अधिकारियों के स्थानांतरण और

तैनाती के लिए एक प्राधिकरण बनाने के वास्ते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, २०२३ लागू किया था, जिससे अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ टकराव शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इसे भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण शहर की सरकार को सौंपने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के साथ "छलावा" करार दिया और एक नई याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया।

दारा सिंह चौहान भाजपा में शामिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देने वाले दारा सिंह चौहान ने सोमवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा राज्य मुख्यालय में चौहान को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई। घोसी (मऊ) विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौहान ने सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को सौंपा था। इससे पहले, चौहान ने २०२२ के विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में वन मंत्री से इस्तीफा देकर सपा की सदस्यता ग्रहण की और मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से वह सपा के टिकट पर निर्वाचित हुए। तब चौहान ने भाजपा सरकार पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सपा के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया लेकिन वहां अपेक्षित महत्व न मिलने से फिर उन्होंने घर (भाजपा में) वापसी कर ली। दो बार क्रमशः बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य्य और वर्ष २००९ में घोसी लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए चौहान ने २०१७ के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। चौहान २०१७ में मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और योगी सरकार में मंत्री बने थे।

उन्होंने भाजपा में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया। चौहान ने कहा कि २०२४ में नरेन्द्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों की सराहना भी की।

शिवसेना यूपी में एक लाख कार्यकर्ताओं को करेगी तैयार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) इकाई

ने पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए राज्य में एक लाख शिवसैनिकों को नामांकित करने का फैसला किया है। नामांकन अभियान के हिस्से के रूप में, पार्टी आगामी बीएमसी चुनावों के लिए समर्थन जुटाने के लिए घर–घर जाएगी और मुंबई में रहने वाले लोगों के परिवारों से संपर्क करेगी। पार्टी सचिव विश्वजीत सिंह ने कहा कि राज्य इकाई यूपी में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगेगी और कांवरियों को फल भी वितरित करेगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर तबादलों में मनमानी का आरोप

लखनऊ। स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में तबादले हो रहे हैं। यह तबादले संगठन के पदाधिकारियों के किये जा रहे हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने बदले की भावना से पदाधिकारियों के तबादले किये गये हैं। दरअसल, स्थानान्तरण नीति–2023 का विरोध कर्मचारी लंबे वक्त से कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसके विरोध में थे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी स्थानान्तरण नीति–२०२३ का विरोध किया गया था। साथ ही उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इस मामले में कर्मचारी संगठनों ने नई स्थानान्तरण नीति पर रोक लगाने की अपील भी की थी। विशेषकर उस नीति पर जिसमें संगठन के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण किये जाने की बात

हो रही थी। इस पर उपमुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के चलते किसी भी पदाधिकारी का स्थानान्तरण नहीं हुआ था, लेकिन स्थानान्तरण का समय समाप्त होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बदले की भावना से संगठन के अध्यक्ष और मंत्री का स्थानांतरण कर दिया है। रायबरेली,हरदोई, बलरामपुर,श्रावस्ती जिलों में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों के तबादले किये गये हैं। यह सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी हैं। इस पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से आग्रह किया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दें कि स्थानांतरण सत्र के समाप्त होने के बाद किए गए स्थानांतरण को निरस्त कराएं । जिससे आपसी सामंजस्य बना रहे वरना आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मणिपुर की हिंसा पर मायावती ने भाजपा पर साधा निशाना

लखनऊ। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। जनजातीय संघर्ष में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। गुरूवार को बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मणिपुर हिंसा पर चिंता जताते हुए एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने राज्य के सीएम को भाजपा की तरफ से संरक्षण देने की बात कही है। मायावती ने अपने ट्वीट में हिंसा के बीच दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्मसार करने वाली बताया है। मणिपुर में अनवरत जारी हिंसा व तनाव से पूरा देश चिन्तित है तथा महिला के साथ अभद्रता की ताजा घटना खासकर भाजपा व उनकी सरकार को

शर्मसार करने वाली है। वैसे तो राज्य में कानून–व्यवस्था काफी पहले से चरमराई हुई है, किन्तु क्या बीजेपी अभी भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी?

अपने खिलाफ मानहानि के मामले को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे कमार आर खान

मुम्बई। कमाल आर खान ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म लक्ष्मी के बारे में अपमानजनक ट्वीट के लिए २०२० में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिवसेना सदस्य राहुल कनाल की शिकायत के आधार पर खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा १५३ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), २९४ (अश्लीलता), ५००, ५०१ (मानहानि) और ५०५ (सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। केआरके के नाम से लोकप्रिय अभिनेता–आलोचक ने २०२० में महामारी के चरम पर दिवंगत अभिनेताओं, इरफान और ऋषि कपूर के खिलाफ भी संदिग्ध ट्वीट किए थे। उच्च न्यायालय के समक्ष

याचिका में खान ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर सभी मामलों में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसने आगे कहा कि खान के खिलाफ एफआईआर संभवतः केवल इसलिए दर्ज की गई थी क्योंकि खान ने उक्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कमाल खान ने कहा कि एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें उनके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप पत्र दाखिल करने सहित एफआईआर को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले किसी भी अन्य कदम पर रोक लगाने की भी मांग की। खान की ओर से पेश वकील अशोक सरावगी और आकाश सिंह ने कहा, श्राय के साथ किसी फिल्म की आलोचना करना कभी भी अपराध नहीं हो सकता।

देश को शर्मसार करने वाले हैवान की सामने आई तस्वीर, मणिपुर पुलिस ने सुबह किया था गिरफ्तार

नई दिल्ली। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने और उनका यौन उत्पीड़न करने वाली भीड़ में शामिल मुख्य अपराधी का पर्दाफाश हो गया है। पेची अवांग लीकाई के रहने वाले ३२ वर्षीय हुइरेम हेरोदास मैतेई को मणिपुर पुलिस के एक अभियान में गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया

गया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा की गई तस्वीरों में गिरफ्तार आरोपी को हरे रंग की शर्ट पहने हुए दिखाया गया है, जो वायरल वीडियो के स्क्रीनग्रैब में भी देखा गया है। मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आने वाले घंटों में और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि दर्ज एफआईआर में बलात्कार और हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। ४ मई को ८००–१,००० उपद्रवियों की सशस्त्र भीड़ द्वारा कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने के भयानक वायरल वीडियो ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैलाया है। यह घटना ४ मई को बी फीनोम गांव में हुई थी। एफआईआर के मुताबिक, पांच लोगों का एक परिवार भीड़ से बचने के लिए जंगल में भाग गया था, जिसने उनके गांव पर हमला किया था, लूटपाट की थी और घरों को जला दिया था। पुलिस ने उन्हें बचाया। मणिपुर के एक गांव में मई महीने में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना पर देशभर में व्याप्त आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस घटना से १४० करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। वहीं, उच्चतम न्यायालय ने इसे ''पूरी तरह अस्वीकार्य'' बताया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वह सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और मृत्युदंड दिलाने का प्रयास भी करेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा, ''मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार वाकई में आगे आए और कार्रवाई करे क्योंकि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। हम सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय देंगे और अगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे।''

राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड का सम्मेलन, GST समेत अन्य मांगों को लेकर दिया ज्ञापन

लखनऊ। व्यापारियों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित गन्ना संस्थान में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नोएडा विधायक पंकज सिंह शामिल हुए। इसके अलावा सम्मेलन में प्रदेश के सभी व्यापारी संघ, व्यापार मंडल और उनके नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान सभी व्यापारी नेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी से चर्चा की। वहीं चेयरमैन सुनील सिंघी और व्यापारी नेताओं ने जीएसटी, व्यापारी सुरक्षा, व्यापारी नीति आयोग का गठन, व्यापारी स्वास्थ्य बीमा, कमर्शियल विद्युत कनेक्शन, कामर्शियल हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, टेस्ट लैब, ई कॉमर्स नीति, ई–कूमर्स पोर्टल जैसी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त

मंत्री सुरेश खन्ना को ज्ञापन सौंपा। जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण जल्द किया जाएगा। साथ ही आवास विकास ने इंदिरानगर एवं राजाजीपुरम में चल रही सीलिंग की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जीएसटी से संबंधी जितनी भी समस्याएं है। उनका सरलीकरण कराया गया है और इसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। साथ ही जीएसटी काउंसिल से पान मसाला पर लगे टैक्स को लेकर वार्ता चल रही है। जिसके नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग, व्यापारी नेता अमर नाथ मिश्र, राजेंद्र अग्रवाल, अनिल बरमानी, संजय गुप्ता, अजय त्रिपाठी मुन्ना, रितेश गुप्ता, जितेंद्र सिंह चौहान, ताज खान, रवींद्र गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, अशोक मोतियानी, संदीप बंसल, नटवर गोयल, ज्ञानेश मिश्रा, अभिषेक खरे, विजय शर्मा और मनीष गुप्ता आदि मौजूद रहे।

घूस नहीं दी तो आवास निरस्त कर करा दिया

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरुवार को आयोजित प्राधिकरण दिवस की अध्यक्षता उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने की। इस दौरान खरगापुर से आईं सावित्री देवी ने बताया कि बसंतकुंज योजना में २००७ में आवास खरीदा था। जिसकी पूरी अदायगी कर दी। आवास की एवज में एलडीए के एक बाबू ने ५० हजार रुपये मांगे थे। जो न देने पर आवास निरस्त कर दूसरे को कब्जा करा दिया। रिपोर्ट में धनराशि बकाया दिखाई। तब से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय न मिला तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि रजिस्ट्री, फ्री–होल्ड, सीमांकन, कब्जा, अवैध निर्माण व एनओसी आदि के कुल ६० मामले आए। जिसमें १६ का मौके पर समाधान किया गया। इस दौरान विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, श्रद्धा चौधरी, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, एसडीएम शशिभूषण पाठक रहे।

इस गाँव की महिलायें साल में पाँच दिन निर्वस्त्र रहती हैं !

अम्रेन्द सहाय अमर

हमारे देश में कई तरह की परंपराओं को अपनाया जाता हैं। हर राज्य की अपनी परंपरा होती है। ऐसी कई परंपराएं हैं, जिन्हें जानकर

आप हैरान हो जाएंगे। सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन भारत में एक जगह ऐसी भी है, जहां की शादीशुदा महिलाएं ५ दिनों तक कपड़े नहीं पहनती है। इन पांच दिनों में वो बिना कपड़ों के ही रहती है। ऐसा सालों से चलता आ रहा है और वो इसे अभी भी निभा रही है। शायद आप विश्वास न करें, लेकिन यह सत्य है कि इस गाँव की महिलाएं साल में पाँच दिन निर्वस्त्र रहती हैं. हालाँकि यह महिलाएं इस दौरान पुरुषों के पास नही आती हैं. इस दौरान महिला का पति भी अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है. महिला को घर के अन्दर ही बंद रहना पड़ता है. इस दौरान इन्हें हंसने मुस्कराने और घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होती है. हमारा देश भारत विविधताओं का प्रदेश है. ना जाने कितनी संस्कृतियाँ, परम्पराएँ इस देश में फलती फूलती और पोषित होती हैं. कुछ विचित्र परम्पराएँ भी फलती फूलती हैं, जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है. आज हम बात कर रहे हैं, हिमांचल प्रदेश के कुल्लू जनपद के मणिकर्ण घाटी के पीणी गाँव की. इस परम्परा को सावन के महीने में निभाया जाता है जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है. कहा जाता है अगर कोई विवाहित महिला इस परम्परा को नही निभाती है, तो उसके घर में अशुभ हो जाता है. इस दौरान विशेष पूजा की जाती है. इन दिनों पुरुष लोग भी तमाम तरह की बुराइयों से दूर भी दूर रहते हैं. यह आयोजन उस घटना की याद में किया जाता है, जब लाहू घोंड देवता ने भाद्रब महीने के पहले एक दिन राक्षस को हराया था. ऐसी जनश्रुति है कि लाहू घोंड देवता जब इस गांव में आए थे, तो यहां उस दौरान राक्षसों ने आंतक मचाया हुआ था, लेकिन देवता के पीणी में आते ही राक्षसों का विनाश हो गया. इसके बाद से ही ये परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी वहां के लोग निभा रहे हैं. कहा जाता है कि सदियों पहले एक राक्षस सुंदर कपड़े पहनने वाली महिलाओं को उठाकर ले जाता थाऔर उनके साथ मनमानी करता था. माना जाता है कि लाहुआ देवता आज भी इस गांव में आते हैं, और बुराइयों से उनकी रक्षा करते हैं. यह परम्परा मनाने की तारीख है, १७ अगस्त से २१ अगस्त. यह परम्परा अभी भी पीढ़ियों से चलती चली आ रही है. इन दिनों महिलाये अपने घर में निर्वस्त्र रहती हैं वे केवल ऊन से बना पट्टू ओढ़कर रहती हैं. इस दौरान पुरुष भी शराब नहीं पीते. मांस भी नही खाते, तमाम तरह की बुराइयों से दूर रहते हैं. लेकिन जैसे–जैसे समय बड़ा है वैसे–वैसे लोगों की कई चीजों में बदलाव देखने को मिला है. अब इस परंपरा का पालन करने के लिए महिलाएं पांच दिन तक कपड़े नहीं बदलती. अब वे एक बेहद पतला कपड़ा पहनती हैं, लेकिन ५ दिन कपड़ों से दूर रहती हैं।

सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान ने ही भारत सरकार को दे दी बड़ी जानकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की ओर से की गयी पूछताछ के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसका पति सचिन मीणा बुधवार को वापस ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा स्थित अपने घर आ गये। घर आने के बाद से दोनों किसी से मिल नहीं रहे हैं। हालांकि घर के बाहर भीड़भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले एक दक्षिणपंथी संगठन की ओर से सीमा के खिलाफ किये गये विरोध प्रदर्शन के चलते घर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गयी है। इस बीच, जांच एजेंसियां सीमा के सच का पता लगाने में जुटी हुई हैं तो दूसरी ओर काठमांडू के जिस होटल में सीमा और सचिन रूके थे, उस होटल वाले ने इन दोनों के बारे में कई नये खुलासे किये हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सीमा हैदर को वापस भेजने के बारे में अंतिम फैसला गृह विभाग लेगा और फिर पाकिस्तान से संपर्क साधा जायेगा। वहीं सीमा का कहना है कि वह पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती क्योंकि वहां कट्टरपंथी उसे पत्थर मार–मार कर मार डालेंगे। सीमा ने यह भी कहा है कि वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती और सचिन के साथ रहना चाहती है। उसने यह भी दावा किया कि उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने देश की सरकार को सूचित किया है कि 'प्यार ही वह एकमात्र' कारक है जिसके कारण चार बच्चों की मां एक हिंदू व्यक्ति के साथ रहने के लिए भारत गई है, जिससे उसकी दोस्ती एक अ नलाइन खेल मंच के माध्यम से हुई थी। जहां तक सीमा के खिलाफ चल रही जांच की बात है तो आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि सचिन ने उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया था जिसको दिखाकर उसने भारत में प्रवेश लिया। सीमा के सिम कार्ड और मोबाइल से डिलिट किये गये डेटा को रिकवर करने का प्रयास भी चल रहा है और जल्द ही सफलता मिलने के आसार हैं जिसके बाद सीमा का सारा सच सामने आ जायेगा। सीमा के बारे में एक बात और पता लगी है कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले उसने जो अपना मकान बेचा था उससे उसे १२ लाख रुपए मिले थे। सीमा से पूछताछ में एटीएस को पता चला है कि सऊदी में काम करते हुए उसका पति गुलाम हैदर हर महीने खर्चे के लिए ७० से ८० हजार पाकिस्तानी रुपये हर भेजता था, जिनमें से वह घर का किराया, बच्चों की फीस और घर के खर्चो के बाद भी हर महीने २० से २५ हजार रुपये बचा लेती थी। इसके अलावा उसने दो लाख रुपये की कमिटी भी डाली हुई थी। जांच में यह भी पता चला है कि सीमा और सचिन ने पबजी पर मुलाकात के १५ दिन बाद ही एक दूसरे को अपने नंबर दे दिये थे। इस बीच, काठमांडू के होटल न्यू विनायक के जिस कमरे में सीमा और सचिन रुके थे उस कमरे को मीडिया को दिखाते हुए होटल मालिक गणेश ने बताया है कि दोनों कमरे में ही रहते थे, सुबह या शाम को बाहर निकलते थे। दूसरी ओर, अभी कुछ दिनों पहले तक जहां सीमा और सचिन को लोग आशीर्वाद देने आ रहे थे वहां अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पड़ोसियों ने चुप्पी साध ली है और मोहल्ले में कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। घर वाले भी मीडिया से नहीं मिल रहे। इस बीच, यह भी खबर मिली है कि भारत आने के बाद सीमा जिस किराये के मकान में रहती थी उसके मालिक ने बताया है कि सीमा के बीड़ी पीने से नाराज होकर अकसर सचिन झगड़ा करता था। दूसरी ओर, सीमा और सचिन के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा देखकर कुछ लोग सुर्खियों में आने का प्रयास भी कर रहे हैं। बुधवार दोपहर भगवा रंग के कपड़े पहन कर तीन कार सवार महिलाएं सचिन के घर के बाहर पहुंचीं। एक ने अपने हाथ में पाकिस्तान विरोधी नारा लिखा बैनर लिया हुआ था। इन महिलाओं ने कार से उतरते ही सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाओश के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने महिलाओं पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए श्जय श्री राम के नारे लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उधर, उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि जब तक 'हमारे पास पर्याप्त सबूत न हों' तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि मई में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली और नोएडा में अपने साथी के साथ रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एक जासूस है। जब प्रशांत कुमार से पूछा गया कि क्या सीमा को निर्वासित किया जाएगा, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इंकार कर दिया। उन्होंने भारत–नेपाल सीमा पर किसी भी सुरक्षा चूक से इंकार किया, जहां से सीमा ने भारत में प्रवेश किया था। उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ प्रक्रिया के बारे में एक अधिकारी ने बताया था कि दंपती को ''गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं'' यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील मामले में पूछताछ के नतीजे पर निर्भर करेगा। स्थानीय पुलिस विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज मामले की अलग से जांच कर रही है, लेकिन इसने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। एटीएस की पूछताछ पर राज्य पुलिस ने कहा कि सीमा हैदर के पास से दो वीडियो कैसेट, चार मोबाइल फोन, पांच 'अधिंत' पाकिस्तानी पासपोर्ट और अधूरे नाम और पते वाला एक 'बिना इस्तेमाल किया गया पासपोर्ट' और एक पहचान पत्र मिला है। यह पूछे जाने पर कि क्या सीमा पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, विशेष डीजीपी ने कहा कि इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, ''मामला दो देशों से जुड़ा है। जब तक हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं हो जाते, तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।'' यह पूछे जाने पर कि क्या नेपाल सीमा के रास्ते भारत में पाकिस्तानी नागरिक का प्रवेश एक सुरक्षा चूक है, कुमार ने कहा, ''ऐसा नहीं है। हमारी सीमा (नेपाल के साथ) खुली है। वहां पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। किसी के चेहरे पर कुछ भी नहीं लिखा है।'' कुमार ने यह भी कहा कि वह भारत में कैसे दाखिल हुई, इसकी जांच के लिए कोई टीम नेपाल नहीं भेजी जा रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या सीमा को निर्वासित किया जा सकता है तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ''इस संबंध में कानून मौजूद है और इसका पालन किया जाएगा। कानूनी आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।'' सीमा और सचिन से एटीएस की पूछताछ पर अधिकारी ने कहा, ''सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं।''

वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, ३५ करोड़ किया जाएगा पौधारोपण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार २२ जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने जा रही है। यूपी में इस बार ३५ करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य बनाया गया है। जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि वृक्षारोपण अभियान में ३५ करोड़ पौधे दो चरणों में लगाए जाएंगे। पहला २२ जुलाई को वृक्षारोपण किया जाएगा। जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज्जफरनगर और बिजनौर में पौधा रौपकर करेंगे। इस दिन पूरे प्रदेश में ३० करोड़ वृक्षारोपण किए जायेंगे। जिसमें पौधा लगाने के लिए प्रदेश के सभी मंत्री, सभी अधिकारी और आम जनमानस को शामिल किया गया है। इसके अलावा १५ अगस्त को ५ करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग

ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ २२ जुलाई को मुजफ्फरनगर के शुक्रताल और बिजनौर में पौधारोपण करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मथुरा में पौधारोपण करेंगी। उन्होंने आगे बताया कि इस बार सभी घरों में फलों के पौधे दिए जाएंगे जिसमें आम, नींबू, अनार, अंगूर, केला, जामुन, अमरूद के पौधे होंगे। वन मंत्री ने आगे बताया कि इस अवसर पर वन विभाग के अलावा सभी सरकारी विभाग, नगर निगम, डिफेंस, रेलवे, समाज सेवी संस्थाओं से पेड़ लगाने को कहा गया है। इसके अलावा आम नागरिक और छात्र छात्राओं से भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की गई है। वन मंत्री ने बताया कि इस बार भी पौधों का वितरण क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं इस अभियान में वन विभाग सर्वाधिक १४ करोड़ पौधे और ग्राम्य विकास विभाग १२.५६ करोड़ पौधे लगाएगा। इसके अलावा इस अभियान में कुल २६ विभाग शामिल होंगे।

मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस् ति का पाताल-पतनः अखिलेश

लखनऊ। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के वीडियो के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर बृहस्पतिवार

को निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मणिपुर की इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, ''मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस्कृति का पाताल–पतन।'' अखिलेश यादव ने मणिपुर के मौजूदा हालात के लिए ''आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की नफरत की नीति और भाजपा की वोट की राजनीति'' को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ट्वीट किया, ''बहन–बेटियों के परिवार वाले अब भाजपा की ओर देखने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे।'' बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने की घटना ''खासकर भाजपा व उसकी सरकार को शर्मसार करने'' वाली है। मायावती ने ट्वीट किया, ''मणिपुर में अनवरत जारी हिंसा एवं तनाव से पूरा देश चिंतित है और महिलाओं के साथ अभद्रता की ताजा घटना खासकर भाजपा एवं उसकी सरकार को शर्मसार करने वाली है।'' उन्होंने कहा, ''राज्य (मणिपुर) में कानून–व्यवस्था काफी पहले से चरमराई हुई है, लेकिन क्या भाजपा अब भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी?'' यह वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि विरोधी पक्ष के कुछ व्यक्ति एक समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lat; cktibZ

lhrkiqj

eks-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

lqjs'k ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk deksj] fcgkj

eks-09386075289

मो० अरशद

C;jks phQ

eÅ

सावन में अमरनाथ पहुंची सारा अली खान

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने कश्मीर में अमरनाथ

की पवित्र गुफ़ा में जाकर बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। सारा अली खान भगवान शिव की भक्त हैं। वह कई बार शिव के दर्शन करने देश के कोने कोने में पहुंचती हैं। सारा सावन के महीने में अमरनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचीं। सारा अली खान के अमरनाथ की यात्रा करने का वीडियो सामने आया है, जहां वह डंडे के सहारे चढ़ाई करती दिख रही हैं। वीडियो में वह यात्रा से लौट रही हैं। डंडे के सहारे वह सीढ़ियों से उतर रही हैं। उन्हें देखकर कई फैंस भी रुक गए। सारा अली खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की थीं। जहां वह खूबसूरत पहाड़ों के बीच पोज देती दिख रही थीं। एक अन्य तस्वीर में वह चाय की चुस्की लेते हुए भी नजर आई थीं।

जहरा खान-टाइगर श्र फ की रोमांटिक केमेस्ट्री के कायल हुए फैंस

मुंबई। बज़ूलीवुड अभिनेता टाइगर श्र फ और अभिनेत्री जहरा एस खान के गाना शलव स्टीरियो अगेनश का टीजर रिलीज हो गया है। भूषण कुमार द्वारा निर्मित लव स्टीरियो अगेन में टाइगर श्र फ

और जहरा एस खान के बीच केमेस्ट्री देखने को मिल रही है। मनीष शंटी द्वारा निर्देशित यह गाना अंतर्राष्ट्रीय संगीत उस्ताद एडवर्ड माया और जाने–माने संगीतकार तनिष्क बागची ने कंपोज किया है।गाने के बोल श्रद्धा पंडित और अंतर्राष्ट्रीय गीतकार एडुआर्ड मैरियन, एल्डार मंसूरोव और क नेवा विक्टोरिया द्वारा लिखे गए हैं। लव स्टीरियो अगेन को २१ जुलाई को टी–सीरीज के यूट्यूब चौनल पर रिलीज किया जायेगा।

एक्टिंग से प्यार करती है जेनेलिया देशमुख, बोलीं– मुझे लगता है कि मेरी यात्रा अद्भुत रही

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख का कहना है कि वह एक्टिंग से प्यार करती है। जेनेलिया देशमुख को फिल्म इंडस्ट्री में आये हुये डेढ़ दशक हो गये है। अपने सिने करियर में जेनेलिया ने हिंदी के अलावा, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया है।जेनेलिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ट्रायल पीरियड को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म की कहानी मॉडर्न फैमिली के इर्द–गिर्द घूमती है, जहां उनके सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। जेनिलिया ने एक यंग मदर का रोल निभाया है। उनका बेटा एक नया पिता चाहता है। आखिरकार, मां बच्चे की जिद पूरी करती है और ट्रायल पीरियड पर एक भाड़े का पापा लाते हैं। वह ३० दिन की अवधि तक उस परिवार के पास रहता

है। जेनेलिया ने बताया, मुझे लगता है कि मेरी यात्रा अद्भुत रही है, क्योंकि एक्टिंग वह करियर नहीं था, जिसे मैंने चुना था। बल्कि, इसने मुझे चुना था। बाद में मुझे इससे प्यार हो गया।मुझे कई लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसके चलते मुझे महसूस हुआ कि मेरी कला में शानदार बदलाव आया है और मैं आगे बढ़ रही हूं।मैं कम ही प्रोजेक्ट चुनना पसंद करती हूं। मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हूं, लेकिन यदि इंतजार करने में इतना समय लगता है तो मुझे इंतजार करने में भी खुशी होगी। अलेया सेन द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म ट्रायल पीरियड में जेनेलिया देशमुख, मानव, शक्ति कपूर, शीबा चड्ढा, गजराज राव और जिदान ब्रेज जैसे कलाकार हैं। ज्योति देशपांडे द्वारा प्रोड्यूस, जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत, क्रोम पिक्चर्स प्रोडक्शन, हेमंत भंडारी, अमित रविंदरनाथ शर्मा और अलेया सेन द्वारा निर्मित ट्रायल पीरियड २१ जुलाई को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक